क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 02 अंक: 20, मंगलवार, 12 फरवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

हर पहलू से गलत है नागरिकता संशोधन विधेयक : यशवंत सिन्हा

गुवाहाटी। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने रविवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक हर पहलू से ''गलत'' है। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा में इस विधेयक के पारित होने के आसार नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा इसे उच्च सदन में पेश करने की ''संभावना नहीं है।'' 'देश की दशा और आगे का रास्ता' विषय पर यहां एक व्याख्यान माला में सिन्हा ने लोगों से अपील की कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को ''एक भी सीट नहीं दें।'' गौरतलब है कि सिन्हा ने पिछले ही साल भाजपा छोड़ी है। सिन्हा ने कहा, ''आप चिंतित हैं कि राज्यसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होगा कि नहीं। मेरा मानना है कि इस समय यह पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी चिंता है। मैंने जिनसे भी बात की है, वे इसे पारित नहीं होने देना चाहते। लिहाजा, मैं नहीं समझता कि सरकार इस विधेयक को पारित करने की हिम्मत दिखाएगी।'' उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि यह इस सत्र में पारित नहीं होगा। तो इस सरकार द्वारा पारित करने का सवाल ही नहीं है।'' पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''यह सरकार फिर से सत्ता में नहीं आने वाली। इसलिए विधेयक की चिंता करने की जरूरत नहीं है।'' उन्होंने कहा, ''यह विधेयक पारित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हर पहलू से गलत है। यह असम एवं पूर्वोत्तर के लोगों के वजूद का सवाल है। यदि कोई आपका वजूद मिटाने की कोशिश करे तो लोग निश्चित तौर पर विरोध करेंगे और इसके खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए पूरा पूर्वोत्तर विरोध प्रदर्शन कर रहा है।'' सिन्हा ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक संवैधानिक, नैतिक, कानूनी और समानता के पहलू से तो गलत है ही, ''देश के मूल्यों के भी खिलाफ'' है।

JDS-कांग्रेस गठबंधन पर मोदी का तंज, कहा- देश पर यही मॉडल थोपना चाहता है विपक्ष

उन्होंने पिछले कुछ समय से सत्तारूढ़ गठबंधन में चल रहे उठापटक पर प्रहार किया मोदी ने कहा, ''हर कोई अपनी सीट बचा रहा है

हुबली ।

कर्नाटक में जद एस-कांग्रेस गठबंधन सरकार पर करारा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी एक ''असहाय'' सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और ''पंचिंग बैग'' बन गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष यही मॉडल देश पर थोपना चाहता है। उत्तर कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि एक भी दिन ऐसा नहीं बीता होगा ''जब देश ने सरकार का नाटक नहीं देखा होगा।'' उन्होंने पिछले कुछ समय से सत्तारूढ़ गठबंधन में चल रहे उठापटक पर प्रहार किया। मोदी ने कहा, ''हर कोई अपनी सीट बचा रहा है। सत्ता के लिए विधायक होटलों में लड़ रहे हैं और सिर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता अपनी प्रभुता के लिए लड़ रहे

हैं।'' मोदी ने कुमारस्वामी का जिक्र करते हुए कहा, ''यहां के मुख्यमंत्री हर किसी का पंचिंग बैग बन गए हैं। हर दिन उन्हें धमकी मिल रही है। उनकी पूरी ऊर्जा कांग्रेस के बड़े नेताओं से अपनी सीट बचाने में लगी हुई है।'' उन्होंने कहा, ''वह सार्वजनिक तौर पर अपनी मजबूरी पर रोते हैं। ऐसी असहाय सरकार, ऐसे असहाय मुख्यमंत्री जिन्हें हर कोई चुनौती दे रहा है। सरकार कौन चला रहा है? इस पर भ्रम बना हुआ है।'' ''मजबूर बनाम मजबूत'' सरकार का नारा देते हुए मोदी ने कहा कि ''कर्नाटक के असहाय मॉडल'' को देश पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है और मेरे खिलाफ विपक्षी दल ''महागठबंधन'' बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी ने कहा, ''वे इसे देश पर थोपना चाहते हैं। इस तरह का असहाय मॉडल, जहां सरकार का मुखिया एक किनारे रोता है और नामदार के महलों में निर्णय किए जाते हैं...वे चाहते हैं कि और भ्रम और सत्ता की लड़ाई जारी रहे और दुनिया देश पर हंसे। वे इस मॉडल को देश पर थोपना चाहते हैं।'' मोदी ने कहा कि ''नया

उन्होंने यहां एक रैली में कहा, ''यह प्रधान सेवक, यह चौकीदार सुनिश्चित करता है कि गरीबों के लाभ सीधे उनके खातों में भेजे जाएं। इसलिए ईमानदार लोग मुझ पर विश्वास करते हैं जबकि भ्रष्ट लोगों को समस्या है''

भारत'' एक मॉडल चाहता है जो मजबूत हो न कि असहाय। उन्होंने कहा कि ईमानदार लोग उन पर विश्वास करते हैं और भ्रष्टाचारियों को उनसे समस्या है क्योंकि उन्होंने सुनिश्चित किया कि गरीबों को मिलने वाला लाभ उन तक सीधा पहुंचे। मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने दलाली का काम किया वे अब भुगत रहे हैं। उन्होंने यहां एक रैली में कहा, ''यह प्रधान सेवक, यह चौकीदार सुनिश्चित करता है कि गरीबों के लाभ सीधे उनके खातों में भेजे जाएं। इसलिए ईमानदार लोग मुझ पर विश्वास करते हैं जबकि भ्रष्ट लोगों को समस्या है।''

अमित शाह का निर्देश, अल्पसंख्यकों से संवाद कायम करें भाजपा नेता

इस बारे में जब विस्तार से बताने को कहा गया तो नाईक ने कहा, अगर आप पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हर किसी को साथ लेकर चलना होगा इसलिए शाह ने अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने के बारे में कहा

पणजी।

लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी नेताओं से कहा है कि वे भाजपा के 'सबका साथ, सबका विकास' मूलमंत्र पर आगे बढ़ते हुए अल्पसंख्यक समुदायों से संवाद कायम करें। उत्तरी गोवा से सांसद एवं केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाईक ने रविवार को ऐसा दावा किया। नाईक के मुताबिक गोवा के पार्टी पदाधिकारियों के साथ शनिवार को बंद कमरे में हुई बातचीत के दौरान शाह ने ये निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया था। नाईक ने संवाददाताओं को बताया, बंद दरावजे के पीछे हुई बैठक के दौरान शाह ने पार्टी नेताओं से अल्पसंख्यकों के बीच जाने को कहा। साथ ही उन्होंने बताया,

नाईक ने संवाददाताओं को बताया, बंद दरावजे के पीछे हुई बैठक के दौरान शाह ने पार्टी नेताओं से अल्पसंख्यकों के बीच जाने को कहा

अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में बात करते हुए शाह सिर्फ गोवा के बारे में ही नहीं कह रहे थे। इस बारे में जब विस्तार से बताने को कहा गया तो नाईक ने कहा, अगर आप पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हर किसी को साथ लेकर चलना होगा। इसलिए शाह ने अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने के बारे में कहा। नाईक ने बताया कि मौजूदा गोवा सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय के सात विधायक हैं जो भाजपा के टिकट पर चुने गए थे। उन्होंने कहा, गोवा में अल्पसंख्यकों के बीच हमारी स्वीकार्यता है। शाह राष्ट्रीय स्तर पर सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे।

विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एक दिन के अनशन पर बैठे चन्द्रबाबू नायडू

नई दिल्ली।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केन्द्र से राज्य को विशेष दर्जा देने और 2014 में इसके विभाजन से पहले किए सभी वादों को पूरा करने की मांग को लेकर सोमवार को यहां एक दिवसीय अनशन शुरू किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित विपक्षी दलों के कई नेताओं के नायडू के समर्थन में यहां पहुंचने की उम्मीद है। तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख आंध्र प्रदेश भवन में अनशन पर बैठे हैं। नायडू ने अनशन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी को राज घाट पर और भीम राव आंबेडकर को

आंध्र प्रदेश भवन में श्रद्धांजलि दी। तेदेपा का एक प्रतिनिधिमंडल नायडू के नेतृत्व में मंगलवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपेगा। आम चुनाव से पहले तेदेपा प्रमुख भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। भाजपा विरोधी गठबंधन के लिए पिछले तीन महीने में वह कई बैठकें कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर तेदेपा मार्च 2018 में राजग सरकार से अलग हो गया था। पार्टी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर पोलावरम सिंचाई परियोजना, कडप्पा इस्पात संयंत्र और निर्माणाधीन अल्ट्रा-आधुनिक राज्य की राजधानी अमरावती के लिए धन नहीं देने का आरोप भी लगाया है। आंध्र प्रदेश को दो जून 2014 को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। हैदराबाद नए राज्य तेलंगाना की राजधानी बन गया।

प्रियंका ने UP के लोगों से कहा, साथ मिल कर हम नयी तरह की राजनीति शुरू करेंगे

नई दिल्ली।

कांग्रेस महासचिव के तौर पर उत्तर प्रदेश की अपनी पहली यात्रा से एक दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राज्य के लोगों के साथ मिल कर वह ''नयी तरह की राजनीति'' शुरू करने की उम्मीद करती हैं, जिसमें हर किसी की हिस्सेदारी होगी। प्रियंका को पूर्वी उप्र का और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उप्र का प्रभारी कांग्रेस महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद सोमवार को राज्य की उनकी यह पहली यात्रा होगी। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी होंगे। पिछले महीने नयी नियुक्तियों की घोषणा होने के बाद ये लोग इस अहम राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रियंका ने कांग्रेस के शक्ति ऐप के जरिए कहा, ''मैं आप सब से

मिलने के लिए कल लखनऊ आ रही हूं। मुझे उम्मीद है कि साथ मिल कर हम नयी तरह की राजनीति शुरू करेंगे, ऐसी राजनीति जिसमें आप सब हित धारक होंगे...मेरे युवा मित्रों, मेरी बहनों और यहां तक कि सबसे कमजोर व्यक्ति, सबकी आवाज सुनी जाएगी।'' तीनों नेताओं के हवाईअड्डे से पार्टी के राज्य मुख्यालय तक की यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रोड शो करने की योजना है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा को राज्य में पार्टी के चुनाव प्रचार के शंखनाद के तौर पर देख रही है। प्रियंका ने कहा, ''आइए, एक नये भविष्य का निर्माण करें, मेरे साथ नयी राजनीति करें। धन्यवाद।'' सिंधिया ने अपने संदेश में कहा, ''कल मैं आपके पास आ रहा हूं। उप्र के युवाओं को भविष्य के लिए एक खाके की और राज्य को बदलाव की जरूरत है। आइए हमारे साथ जुड़िये और उत्तर प्रदेश में बदलाव लाइए।'' कांग्रेस के दोनों महासचिव 12,13 और 14 फरवरी को लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे।

मायावती का मुख्य उद्देश्य अपनी मूर्तियां लगवाना था : रामविलास पासवान

नयी दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने रविवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते बी आर आंबेडकर समेत विभिन्न दलित नेताओं की मूर्तियां स्थापित करने के पीछे मायावती का असल मकसद खुद की प्रतिमाएं लगवाना था। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) अध्यक्ष पासवान का बयान उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी की पृष्ठभूमि में आया है। शीर्ष अदालत में नेताओं द्वारा अपनी तथा पार्टी के चुनाव चिन्ह की मूर्तियां स्थापित करने में जनता का पैसा खर्च करने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी।

मेरे क्षेत्र में जातिवाद की बात करने वालों की होगी पिटाई : नितिन गडकरी

पुणे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि उनके क्षेत्र में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी हुई है कि जाति के बारे में बात करने वाले की वह पिटाई करेंगे। यहां पिंपड़ी चिंचवाड़ में पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि समाज को आर्थिक एवं सामाजिक समानता के आधार पर साथ लाना चाहिए और इसमें जातिवाद एवं सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नागपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले गडकरी ने कहा, हम जातिवाद में यकीन नहीं करते हैं...मुझे नहीं पता कि आपके यहां क्या है लेकिन हमारे पांच जिलों में जातिवाद की कोई जगह नहीं है क्योंकि मैंने सभी को चेतावनी दी हुई है कि अगर कोई जाति की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा।

उरी में एक बार फिर बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी, सेना ने साजिश की नाकाम

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षाबलों के जवानों सेना कैंप पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बीती रात उरी के राजारवानी में सेना की आर्टिलरी यूनिट (19 डिवीजन) पर तैनात संतरी ने संदिग्ध हरकत दिखने पर तुरंत फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई है। इसके बाद आतंकियों की खोज के लिए से पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में कुछ आतंकी मारे गए है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी का शव नहीं मिला है। पुलिस और सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ज्वाइंट टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही यह भी सूचना है कि इलाके के नल्लाह के पास दो लोगों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पांच आतंकवादी ढेर 10 फरवरी को जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के पांच आतंकवादी मारे गये थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने रविवार की सुबह जिले के कल्लेम गांव में सुरक्षाबलों के तलाशी दल पर गोलियां चलाई जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में पांच आतंकवादी मारे गए और मौके से हथियार एवं युद्ध संबंधी सामग्री बरामद की गई।पुलिस अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान वसीम अहमद राथर, अकीब नजीर मीर, परवेज अहमद भट, इद्रिस अहमद भट और जाहिद अहमद पारें के तौर पर हुई है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया, ÷पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, यह हिजबुल मुजाहिदीन एवं लश्कर-ए-तैयबा और उनके आतंकवादियों का समूह था। सही-सही संबद्धता के बारे में पता लगाया जा रहा है।

रविशंकर प्रसाद बोले, राफेल फोबिया से पीड़ित हैं राहुल गांधी

हैदराबाद।

भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह देश की सुरक्षा के साथ काफी ''गैर जिम्मेदाराना तरीके से'' खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री पर अक्सर निशाना साधते आ रहे हैं। गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लड़ाकू विमान के सौदे पर वह ''बेशर्मी से झूठ'' बोल रहे हैं और उन्हें ''राफेल फोबिया'' हो गया है। प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''राहुल गांधी को राफेल फोबिया है... प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस

तरह की भाषा का वह इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उन्हें शोभा नहीं देता।'' गांधी परिवार के सदस्यों पर लगे कथित भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र करते हुए प्रसाद ने कहा, ''बोफोर्स मामले में उनके पिता (राजीव गांधी) पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे?... उनकी दादी इंदिरा जी (पूर्व प्रधानमंत्री) के भ्रष्टाचार के क्या रिकॉर्ड रहे हैं? हमने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह की भाषा वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं।'' केंद्रीय कानून, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पर राफेल सौदे को अंतिम रूप नहीं देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इसे फिर समीक्षा के लिए भेज दिया गया क्योंकि पार्टी कोई भी ऐसा समझौता नहीं करती जिसमें उसे ''कमीशन'' नहीं मिलता है। उन्होंने कहा, ''चूंकि उन्हें कमीशन नहीं मिला इसलिए उन्होंने इसे (सौदे) लंबित रखा।'' 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी ने राफेल सौदे को जारी रखने का निर्णय किया क्योंकि भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों की जरूरत है।

मतदाता सूची मामला: आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप

नई दिल्ली। चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली के लोगों को मतदाता सूची के संबंध में भ्रामक कॉलों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस से कहने के कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के दफ्तर में तब्दील हो गया है, जिससे आप और भगवा दल में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आप की मान्यता रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी आप के स्वयंसेवक लोगों को फोन करके बता रहे हैं कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है और पार्टी संयोजक उन्हें फिर से जोड़ रहे हैं।

पुलिस आपकी, श्रेष्ट आपका - उनसे इस तरह गलत और गंदे काम मत करवाइए। ये देश किसी एक व्यक्ति और पार्टी से बहुत बड़ा है केजरीवाल ने ट्वीट किया, ''चुनाव आयोग को भाजपा कार्यालय में बदलने के लिए आपके चुनाव आयुक्तों को इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्मनाक, मोदीजी हर संस्थान को नष्ट कर रहे हैं। हम भाजपा को उसकी साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे।'' उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और उनसे कहा कि चुनाव आयोग और पुलिस को गलत, गंदे कृत्यों में लिप्त न करें, और कहा कि देश किसी भी पार्टी या व्यक्ति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तिवारी ने आप पर लोगों को 'गुमराह' करने और समाज में 'अशांति' पैदा करने का आरोप लगाया।

फंस गई आप ! भ्रामक फोन कॉल्स के खिलाफ दिल्ली चुनाव आयोग ने पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। कॉल्स करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। भ्रामक फोन कॉल्स को लेकर लोगों ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। उन्होंने ट्वीट किया, '' भारत के संविधान का सम्मान नहीं करने वाले एक राजनीतिक दल द्वारा गंभीर अपराध किया गया है। नागरिकों को गुमराह करने और समाज में अशांति पैदा करने की कोशिश के लिए आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस को कई प्राथमिकियां दर्ज करनी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए।''

राफेल को लेकर कांग्रेस ने कैग पर दागे सवाल

कपिल सिब्बल के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ''झूठ के आधार पर कैग की संस्था पर आक्षेप लगा रही है

नई दिल्ली।

हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने रविवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) राजीव महर्षि से अनुरोध किया कि वह 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के करार की ऑडिट प्रक्रिया से खुद को अलग कर लें, क्योंकि तत्कालीन वित्त सचिव के तौर पर वह इस वार्ता का हिस्सा थे। कपिल सिब्बल के इन आरोपों पर

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ''झूठ' के आधार पर कैग की संस्था पर आक्षेप लगा रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि महर्षि का संसद में राफेल पर रिपोर्ट पेश करना अनुचित होगा। सोमवार को संसद में विवादित राफेल करार पर कैग रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। जेटली ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके कहा, 'संस्थानों को बर्बाद करने वालों' द्वारा झूठ को आधार बनाकर कैग की संस्था पर एक और हमला। दस साल सरकार में रहने के बावजूद संप्रग सरकार के पूर्व मंत्रियों को अब तक नहीं पता कि वित्त सचिव महज एक पद है जो वित्त मंत्रालय के वरिष्ठतम सचिव को दिया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने इससे पहले कहा था कि महर्षि 24 अक्टूबर 2014 से लेकर 30 अगस्त 2015 तक वित्त सचिव थे और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अप्रैल 2015 को पेरिस गए और राफेल करार पर दस्तखत की घोषणा की।कांग्रेस नेता ने कहा, 'वित्त मंत्रालय इन वार्ताओं में अहम भूमिका निभाता है। अब स्पष्ट है कि राफेल करार राजीव महर्षि के इस कार्यकाल में हुआ। अब वह सीएजी के पद पर हैं। हमने 19 सितंबर 2018 और चार अक्टूबर 2018 को उनसे मुलाकात की। हमने उन्हें घोटाले के बारे में बताया। हमने उन्हें बताया कि करार की जांच होनी चाहिए क्योंकि यह भ्रष्ट तरीके से हुआ, लेकिन वह अपने ही खिलाफ कैसे जांच करा सकते हैं?' इलाज के बाद अमेरिका से लौटे जेटली ने कहा कि वित्त सचिव वित्त मंत्रालय के वरिष्ठतम सचिव को दिया जाने वाला पद है और राफेल फाइल की प्रक्रिया में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

संपादकीय

उत्तरप्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में दिखा जहरीली शराब का कहर प्रशासनिक लापरवाही का जीता-जागता सबूत है। उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में शराब की बिक्री जारी है, मगर बिहार में अगर शराब पीने से लोग मर रहे हैं, तो यह सरकार पर भी सवालिया निशान है। हमारी सरकारें जब तक शराब को कमाई का जरिया मानती रहेंगी, तब तक शराब के धंधे में लगे लोगों पर कार्रवाई का न तो असर होगा और न ही लोगों में चेतना जागृत होगी।

शराब पर नीति-नीयत बदलें सरकारें

उत्तरप्रदेश, बिहार व उत्तराखंड में दिखा जहरीली शराब का कहर प्रशासनिक लापरवाही का जीता-जागता सबूत है। उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में शराब की बिक्री जारी है, मगर बिहार में अगर शराब पीने से लोग मर रहे हैं, तो यह सरकार पर भी सवालिया निशान है। हालांकि, शराब की बिक्री अब भी उन राज्यों में जारी है, जहां वर्षों से शराबबंदी है, लेकिन इससे न तो बिहार को क्लीनचिट मिल जाती है और न ही उन राज्यों को जहां शराब बेचकर सरकारी खजाने को दिन दूना और रात चौगुना भरा जा रहा है। तीनों राज्यों में जहरीली शराब का सेवन करने से सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। यूपी में कुल 75 तो उत्तराखंड में 32 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 11 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। बिहार में भी तीन की मौत हुई है। लाख दावों के बाद भी जहरीली शराब के कारोबार पर अंकुश नहीं लग सका है। गांव-गांव कच्ची शराब बनती और बिकती है, पर आश्चर्य है कि पुलिस और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती या यूं कहें कि समूचे तंत्र की शह पर ही मौत का यह कारोबार पनपता है।

जिन राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू है, वहां भी और जहां धड़ल्ले से शराब बिक रही है, वहां भी लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। मगर हमारे नीति-नियंताओं की पेशानी पर बल नहीं दिख रहा है। सरकार और प्रशासन की लापरवाही का शिकार अब उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के वे लोग हुए हैं, जो जहरीली शराब पीकर मर चुके हैं और उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। जहरीली शराब को लेकर स्थिति इतनी विकट है कि समय-समय पर हर राज्य में किसी न किसी की मौत हो जाती है। वैसे, इस कारोबार के लिए सिर्फ पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। राजनीतिक नेतृत्व भी इसके लिए जिम्मेदार है। पार्टी और सरकार कोई भी हो, कभी किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कई नेता तो बाकायदा चुनाव में जीत के लिए अवैध शराब को हथियार बनाते हैं। गरीब-गुरबों को बहलाकर शराब पिलाई जाती है और इस आड़ में अनैतिक काम भी कराए जाते हैं। पीढ़ियां चौपट हो रही हैं, बच्चे स्कूल जाने के बजाय शराब बनवाते हैं और फिर वही उनका पेशा बन जाता है। पीने वाले आसपास का माहौल खराब करते हैं। अपने घरों का माहौल भी बिगाड़ते हैं। सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या पर अंकुश लगाए, ताकि लोगों को बेमौत मरने से रोका जा सके और समाज का भला हो।

जब तक सरकारों की मौजूदा नीतियां कायम रहेंगी, तब तक शराब की लत की चपेट में आने से लोगों को नहीं बचा सकते हैं। अगर हर गली नुक्कड़ पर शराब की दुकानें खोल देंगे, तो लोग ज्यादा सेवन करेंगे ही। जहां शराब बंदी करने का दिखावा किया जाता है, वहां अवैध बिक्री शुरू हो जाती है और फिर खराब गुणवत्ता वाली शराब बिकने लगती है, जो जानलेवा साबित होती है। शराब के आदी लोग ज्यादा दाम पर भी घटिया शराब पीने लगते हैं, जो मौत के करीब ले जाती है। वैसे भी हर सरकार की कोशिश रहती है कि राजस्व बढ़ाने के लिए शराब के धंधे का ज्यादा से ज्यादा दोहन कर ले। जाहिर है, ऐसे में लोगों को नशे या जहरीली शराब से बचा पाना संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था, 'अगर मैं एक दिन के लिए तानाशाह बन जाऊं, तो बिना मुआवजा दिए शराब की दुकानों और कारखानों को बंद करा दूंगा।' गांधीजी ने पूरी सूझबूझ के साथ यह बात कही थी, क्योंकि बर्बादी का बड़ा कारण यह शराब ही है। कुछ वर्षों पहले केरल सरकार ने राज्य में शराबबंदी का ऐलान कर इस मुद्दे पर फिर बहस छेड़ दी थी। केरल के बाद बिहार वह राज्य बना, जिसने अपने राज्य में पूर्ण शराबबंदी की। लेकिन सच यह भी है कि पूर्ण शराबबंदी को लागू करना प्रदेश सरकारों के लिए संभव ही नहीं रहा। जिस भी राज्य में शराबबंदी लागू की गई, वहां शराब की तस्करी बढ़ गई।

देश में सबसे पहले महाराष्ट्र में शराबबंदी लागू हुई। इसकी खिलाफत में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अप्रैल, 1950 में मुंबई के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने राज्य में शराब पर बैन लगाया, तो अदालत में व्यक्तिगत आजादी के आधार पर अधिनियम को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने द स्टेट औफ बौंबे वर्सेज एफएन बालसरा मामले में 1951 में फैसला सुनाते हुए अुनच्छेद 47 की विस्तार से व्याख्या की कि जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार तथा राज्य के द्वारा शराबबंदी लागू करने में कोई परस्पर विरोध नहीं है। साथ ही शीर्ष अदालत ने अलकोहल का औषधीय प्रयोग और साफ-सफाई के रसायन के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। इस समय देश में गुजरात, मिजोरम, बिहार व नगालैंड ऐसे प्रदेश हैं, जहां पूर्ण शराबबंदी है। गुजरात में तो आजादी के बाद से ही शराब पर पाबंदी है, मगर अफसोस यह महज कहने को ही है। वहां शराब हर जगह आसानी से उपलब्ध है। अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस महकमा हर साल सवा सौ करोड़ की अवैध शराब जब्त करता है। हर साल जहरीली शराब पीने से मौत होती हैं। 2009 में गुजरात में जहरीली शराब पीने से 148 लोग मारे गए थे।

मिजोरम राज्य में 1995 में शराबबंदी का कानून पारित किया गया था। मगर अगस्त, 2014 में शराबबंदी खत्म करने का फैसला कर नया कानून पारित कर दिया गया। सरकार का मानना था कि शराबबंदी से लाभ कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। नागालैंड में भी इसी समय से शराबबंदी लागू है। गौरतलब है कि देश में सब से ज्यादा शराब की खपत केरल में ही होती है। राज्य को 22 फीसदी राजस्व शराब से ही हासिल होता है। जब तक सरकारों की मौजूदा नीतियां कायम रहेंगी, तब तक शराब की लत की चपेट में आने से लोगों को नहीं बचा सकते। इस मामले में भारत को सिंगापुर से सीखना चाहिए। वहां सिगरेट के सेवन से सेहत पर होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने बाकी देशों से सिगरेट की सात गुना ज्यादा कीमत तय कर दी है। इससे लोगों ने सिगरेट खरीदना कम कर दिया है। सिगरेट के पैकेटों पर भयानक चेतावनी छापने के साथ-साथ सजा भी तय कर दी गई है। इस से लोगों में डर पैदा हो गया है। उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीना बंद कर दिया है। सिगरेट का पैकेट फेंकते पकड़े जाने पर भी जेल भेज दिया जाता है।

लेकिन हमारे यहां तो सरकारों की नीतियां सिगरेट पीने से रोकने के बजाय उन्हें सहजता से उपलब्ध कराने वाली हैं। फिर शराब की बात कुछ और है। ऐसे में समाज का तानाबाना टूटना लाजिमी है। यदि सरकारें उपलब्धता पर नियंत्रण करें, तब ही लोगों को इन के सेवन से रोका जा सकता है। दरअसल, शराब का असली नशा तो इस धंधे की कमाई की चाशनी में डूबने वालों पर ही ज्यादा चढ़ता है। फिर चाहे वे सरकारें हों या शराब का धंधा करने वाले। सभी चाहते हैं कि शराब से उन की तिजोरियों की सेहत हर दिन दुरुस्त होती रहे। प्रशासन की सरपरस्ती में शराब का कानूनी व गैरकानूनी धंधा खूब फल-फूल रहा है, जिस में पुलिस, सरकार सब शामिल हैं। सरकार के पास पढ़े-लिखे, अनपढ़ और अमीर-गरीब, हर तबके के लिए देशी से ले कर अंग्रेजी शराब तक का बंदोबस्त है। शराब को घर-घर पहुंचाने के लिए गांवों व शहरों में ठेका देने का काम भी बड़ी सूझबूझ के साथ किया जाता है ताकि कोई इलाका अछूता न रह जाए। दरअसल, पैसे कमाने की सहूलियत के लिए इसे कानूनी और गैरकानूनी बता दिया गया है यानी जो सरकार बेचे, वह कानूनी है और जिस से उस का फायदा न हो, वह गैरकानूनी। यही समस्या की असल जड़ है।

हरिमोहन उपाध्याय
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

विचार

गुर्जर आंदोलन ने दिखाए तेवर

राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति फिर सड़कों पर है। आंदोलन करना गलत नहीं है। आंदोलन शांति पूर्वक हो तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं है। मगर अब यह समाज व देश के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। सरकार गुर्जरों से बात कर आंदोलन खत्म कराए।

राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति फिर सड़कों पर है। नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर उसने कई जगहों पर रेल व सड़क परिवहन को ठप कर रखा है। दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर चलने वाली अनेक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और उनके मुसाफिरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुर्जरों का यह आंदोलन पहली बार नहीं दिखा है। समय-समय पर गुर्जर समाज आरक्षण की मांग को लेकर आपे से बाहर दिखा है, क्योंकि अतीत में उनके लिए हुए आरक्षण के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। स्टे इसलिए लगा था क्योंकि गुर्जरों के लिए पांच फीसदी सीटें आरक्षित करने से कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा लगा रखी है। अतः गुर्जरों को आश्वस्त करना सरकार के लिए अब आसान नहीं है। उन्हें 50 फीसदी कोटे के अंदर आरक्षण दिया जाता है, तो उससे वे जातियां नाराज होंगी, जिनके हिस्से से ये सीटें जाएंगी।

गुर्जरों के आंदोलन की आंच वसुंधरा सरकार, उससे पहले गहलोत सरकार और अब फिर गहलोत सरकार को झुलसा रही है। इसी से पता चल जाता है कि गुर्जर कितने समय से अपनी मांग को लेकर नाराज हैं, मगर समाधान आज तक नहीं हो सका है। एक समय गुर्जरों ने खुद को अनुसूचित जनजाति घोषित करने तक की मांग की थी। इससे राजस्थान की मीणा जनजाति से उनका टकराव शुरू हो गया था। वैसे भी संविधान के तहत जनजाति की खास परिभाषा है। सरकारें मनमर्जी से इस प्रावधान में बदलाव नहीं कर सकतीं। इसीलिए पहले राजस्थान की भाजपा नीत वसुंधरा राजे सरकार और अब भाजपा नीत अशोक गहलोत सरकार के सामने गहरी उलझन है। अब यदि आंदोलन को सामाजिक नजरिए से देखें, तो जनता को भी आंदोलन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रेल व सड़क यातायात ठप होने से आम लोगों को इससे परेशानी हो रही है। दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। सरकार को चाहिए कि वह गुर्जरों के साथ बातचीत करे और आंदोलन समाप्त कराए। नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों के आंदोलन का असर हर बार रेल और सड़क मार्ग पर ही पड़ता है।

किसी बात को लेकर आंदोलन करना गलत नहीं है, लेकिन यदि आंदोलन शांति पूर्वक हो तो किसी को इसमें आपत्ति भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से गुर्जर संघर्ष समिति के पदाधिकारी इस आंदोलन को उग्र बनाते जा रहे हैं, उससे देश के साथ-साथ देश के लोगों को भी भारी नुकसान हो रहा है। गुर्जरों को चाहिए कि वह अपना आंदोलन शांति पूर्वक करें जिससे आमजन को तकलीफ न हो। वैसे आजादी के बाद से सभी जातियों का विकास हुआ है, लेकिन कुछ दल चुनाव से पहले इस तरह के आश्वासन दे देते हैं, जो चुनाव बाद पूरे नहीं हो पाते हैं और समाज के लोग राजनीतिक दलों पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। गुर्जरों का आंदोलन भी इसी का परिणाम है।

बच्चों की चिंता करे समाज

अब बाल विवाह को लेकर सोच में परिवर्तन आ रहा है। समाज में शिक्षा के प्रसार और आर्थिक स्थिति में सुधार का असर बाल विवाह की संख्या में कमी के तौर पर नजर आ रहा है। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड में इसमें उल्लेखनीय सुधार नजर आ रहा है। लेकिन अब भी काफी प्रयास किए जाने शेष हैं। माता-पिता और समाज को अपने स्तर पर बच्चों के भविष्य की चिंता करनी ही होगी।

आखातीज या अक्षय तृतीया को अबूझ सावे के रूप में जाना-पहचाना जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में विवाह होते हैं जिनमें बाल विवाह भी शामिल है। बाल विवाह का मतलब छोटी आयु में शादी। यानी 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह होना, बाल विवाह माना जाएगा। भारत में बाल विवाह की प्रथा काफी पुरानी थी। लाख कोशिशों के बाद भी अपने देश से यह कुप्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई। सभ्य समाज के मुंह पर यह एक तमाचा है। यह मानव जीवन की सबसे बड़ी और दुखद त्रासदी है। यह सामाजिक बुराई हिंदी और अहिंदी भाषी दोनों तरह के राज्यों में समान रूप से प्रचलित है। विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाल विवाह का चलन आज भी है। मगर अब बदलाव दिख रहा है। इसका श्रेय सरकार को दिया जाए या समाज को अभी इस पर निष्कर्ष निकालना जल्दी होगा। मगर संतुष्टि यह है कि अब बाल विवाह को लेकर सोच में परिवर्तन आ रहा है। समाज में शिक्षा के प्रसार और आर्थिक स्थिति में सुधार का असर बाल विवाह की संख्या में कमी के तौर पर नजर आ रहा है। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड में इसमें उल्लेखनीय सुधार नजर आ रहा है।

उत्तर प्रदेश तो इस लिहाज से चैंपियन स्टेट की तरह उभरकर आया है और 15 से 19 साल की उम्र में सिर्फ 6.4 फीसदी लड़कियों की ही शादी हो रही है। हालांकि, बंगाल में स्थिति चिंताजनक है। कम उम्र में विवाह का बुरा प्रभाव किशोरियों के गर्भवती होने का है। बाल विवाह की दर में ज्यादातर राज्यों में कमी आई है पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां अन्य राज्यों की तुलना में सुधार अपेक्षाकृत काफी कम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-चार (2015-16) के अनुसार, देश में बाल विवाद की औसत दर 11.9 फीसदी है। हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में आंकड़ों में कुछ वृद्धि जरूर दर्ज की गई है। एनएफएचएस तीन (2005-06) के आंकड़ों से एनएफएचएस-चार (2015-16) के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में काफी सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में 29 फीसदी से दर कम होकर सिर्फ 6.4 फीसदी ही रह गया है। पश्चिम बंगाल में भी सुधार हुआ है, मगर कम है। बंगाल में 34 फीसदी से यह दर कम होकर 25.6 फीसदी रह गई है।

बाल विवाह का दुष्प्रभाव कम उम्र में गर्भधारण के रूप में भी है। 15 से 19 की उम्र में शादी होने वाली लड़कियों में हर तीन में से एक लड़की टीन-ऐज में ही मां बन जा रही है। इस उम्र में शादी होने वाली लड़कियों में से एक चौथाई 17 साल की उम्र तक मां बन जाती हैं और 31 फीसदी 18 की उम्र तक मां बन जाती हैं। टीन-ऐज प्रेगनेंसी में गोवा पहले नंबर पर है, मिजोरम दूसरे और मेघालय तीसरे नंबर पर है। बाल विवाह को लेकर शहरों की स्थिति गांवों से बेहतर है और इसी तरह आर्थिक आधार भी बाल विवाह रोकने के लिहाज से अहम फैक्टर है। शहरों में बाल विवाह का औसत 6.9 फीसदी और गांवों में 14.1 फीसदी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां शहरों में बाल विवाह के आंकड़े चौंका सकते हैं। शहरी क्षेत्र में विवाह में पहला नंबर हरियाणा का है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पर मणिपुर का नंबर आता है। दरअसल, छोटी आयु में विवाह का मुख्य कारण सिर्फ अशिक्षा व गरीबी है। अभिभावक गरीबी के कारण बेटी का जल्दी विवाह कर सामाजिक दायित्व से निवृत्त होना चाहते हैं।

नासमझी और अशिक्षित होने के कारण उन्हें यह ज्ञान नहीं रहता कि वे अपनी बेटी को एक अंधे कुएं की ओर धकेल रहे हैं जिसमें से वह ताउम्र नहीं निकल पाएगी। छोटी आयु में विवाह के कारण लड़की को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। खेलने-कूदने के दिनों में वह घर-गृहस्थी की समस्याओं से जूझती रहती है। इसके अलावा, उसे घरेलू हिंसा का सामना भी करना पड़ता है। फिर शारीरिक रूप से अपरिपक्वता के साथ उसे शिक्षा से भी वंचित होना पड़ता है। बाल विवाह को सख्ती से रोकने के लिए अनेक स्तरों पर प्रयास किए गए। यह सदियों पुरानी कुप्रथा है जिसे जाने अनजाने हम आज भी भले ही कम, मगर ढोते चले आ रहे हैं। 1928-29 में शारदा एक्ट बना, जिसमें नाबालिग बच्चों के विवाह को निषिद्ध किया गया। भारत सरकार ने इस कानून की पालना के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष व लड़की की आयु 18 वर्ष निर्धारित की थी। इससे कम आयु के बच्चों का विवाह कानूनी रूप से निषिद्ध और दंडनीय अपराध स्वीकारा गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 में बाल विवाह को दंडात्मक अपराध माना गया है।

रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 प्रतिशत बाल विवाह भारत में होते हैं। इनमें 49 प्रतिशत लड़कियों के विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो जाते हैं। लिंग भेद वर अशिक्षा सबसे बड़ा कारण माना गया है। यूनिसेफ के अनुसार राजस्थान में 82 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले हो जाता है। 1978 में संसद द्वारा बाल विवाह निवारण कानून पारित किया गया था। इसमें विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। यूनिसेफ की बच्चों संबंधी एक और रिपोर्ट में यह बताया गया है 47 प्रतिशत महिलाएं कानूनी रूप से 18 वर्ष से कम आयु में ब्याही गईं। इनमें 56 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की थीं। बाल विवाह आज भी ज्वलंत समस्या के रूप में हमारे सामने है। यह अनादिकाल से चली आ रही है। सामाजिक मान्यता मिलने के कारण इसे बढ़ावा मिलता रहा है। इसी कारण इस कुप्रथा ने विकराल रूप धारण कर लिया। अशिक्षा व अज्ञानती का वजह से कुछ लोग इस कुप्रथा को अब भी ढोए जा रहे हैं। बाल विवाह को बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन भी माना गया है। जब तक बच्चे बालिग या समझदार न हो जाएं और अपने भले-बुरे की पहचान के योग्य न हो जाएं, तब तक विवाह नहीं किया जाना चाहिए।

यह भी वैज्ञानिक परिणामों से स्पष्ट है कि बाल विवाह से अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा का अधिकार, खेलने-कूदने के अवसर हासिल नहीं होते। कच्ची उम्र में शादी होने से स्वास्थ्य और जननांगों पर भी खराब असर पड़ता है जिसे बच्चों को ताउम्र झेलना पड़ता है। फिर छोटी उम्र में विवाह से लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा अधिक हानि उठानी पड़ती है। असुरक्षित यौन संबंधों से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप अनेक भीषण बीमारियों से ग्रस्त होना आम बात है। बाल विवाह के कारण बार-बार गर्भधारण और असमय गर्भपात का सामना करना पड़ता है और नवजात शिशु के भी अकाल मौत का शिकार होने का अंदेशा बना रहता है। कुपोषण और खून की कमी से मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह के समर्थक इसके पक्ष में अनेक कुतर्कों का सहारा लेकर समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अनेक अभिभावक यह मानते हैं कि जल्दी विवाह से लड़कियों को यौन हिंसा से बचाया जा सकता है।

सामाजिक चेतना के अभाव और कानून की शिथिलता के कारण निश्चय ही बाल विवाह की सामाजिक कुरीति को बढ़ावा मिलता है। बाल विवाह को रोकने के लिए समाज में जनचेतना के प्रयास किए जाने बेहद आवश्यक हैं। पिछले कुछ दशकों से इस दिशा में किए गए प्रयासों का असर देखने को मिला है। शिक्षित समाज ने इस सामाजिक बुराई को समझा है। मगर ग्रामीण तबका आज भी बाल विवाह का पक्षधर है। इस तबके को समझाने के लिए सभी संभव प्रयास करने होंगे। इसके लिए बुजुर्गों का सहयोग जरूरी है।

किरण सक्सेना
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

ट्विटर

हम यहां तब तक डटे रहेंगे जब तक कोई फैसला नहीं ले लिया जाता है। सरकारें हमें बार-बार झूठा आश्वासन देकर बेवकूफ बना रही हैं, मगर इस बार नहीं।

किरोड़ी सिंह बैंसला, गुर्जर नेता

गुर्जरों की मांग पूरी करना हमारी प्राथमिकता है और हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मगर गुर्जरों को इस तरह आंदोलन बंद करना चाहिए, जिसमें देश का अहित हो।

सचिन पायलट, उपमुख्यमंत्री राजस्थान

सत्यार्थ

सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दें

एक बार की बात है। फ्रांस में विद्वानों के द्वारा वहां के नागरिकों से लेख आमंत्रित किए गए। सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी। एक लेख नेपोलियन ने भी भेजा था। नेपोलियन के लेख को ही सर्वश्रेष्ठ लेख घोषित किया गया। कुछ समय के बाद नेपोलियन वहां के सम्राट बन गए, लेकिन वे इस बात को लगभग भूल चुके थे। नेपोलियन का एक मंत्री था टेलीरांत। उसको इस बात की जानकारी कहीं से मिल गई कि सम्राट नेपोलियन ने एक लेख लिखा था, जो पुरस्कृत हुआ था। इसलिए उसने अपने एक विशेष व्यक्ति को भेजकर उस लेख की मूल प्रति मंगवा ली। एक दिन उसने उस मूल प्रति को नेपोलियन के सामने रखकर हंसते हुए पूछा कि सम्राट, क्या इस लेख के लेखक को आप जानते हैं? तब नेपोलियन उस लेख को देखकर कुछ सोचने लगे। उनकी मुद्रा देख टेलीरांत ने सोचा कि सम्राट खुश होंगे व उसे पुरस्कार देंगे। कुछ देर सोचने के उपरांत सम्राट नेपोलियन ने उस प्रति को अपने हाथ में लिया और उसको लेकर कमरे में जल रही अंगीठी के पास गए। वह कुछ देर उसे देखते रहे। फिर अंगीठी में उस लेख को डाल दिया। लेख जल गया। टेलीरांत समझ नहीं पाया कि नेपोलियन ने ऐसा क्यों किया। तब उसने नेपोलियन से पूछा-सम्राट, इस लेख को आपने क्यों जला दिया है? नेपोलियन बोले-यह लेख मेरे एक समय की उपलब्धि थी, मगर आज इसका कोई महत्व नहीं रहा। अतः मैंने इसे जला दिया। अब टेलीरांत समझ गया कि देश व काल की परिस्थितियों में चिंतन को नया रूप देते रहना चाहिए। ऐसा न हो कि हम पुरानी प्रशंसाओं में ही डूबे रहें। इसीलिए हमें अच्छे-बुरे पुराने अनुभवों को भूलकर वर्तमान पर ही ध्यान देना चाहिए।

राधा नाचीज

वोडाफोन आइडिया की नेटवर्क पर 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना

नई दिल्ली।

देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के अपने नेटवर्क पर अगले 15 महीने के दौरान 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। कंपनी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वोडाफोन के मुख्य वित्त अधिकारी अक्षय मुंद्रा ने विश्लेषकों से टेली-कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए पूंजीगत खर्च के रूप में कुल 270 अरब रुपए दिए हैं। इसमें करीब 70 अरब रुपए पहले नौ महीनों में खर्च किए गए हैं। अगले 15 महीनों में 200 अरब रुपए का निवेश करने की योजना है। कंपनी की राइट इश्यू के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी योजना है। कंपनी के प्रवर्तक शेयरधारकों वोडाफोन समूह और आदित्य बिड़ला समूह ने निदेशक मंडल की बैठक में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि वह प्रस्तावित राइट इश्यू में अपनी हिस्सेदारी के तौर पर क्रमशः 11,000 करोड़ रुपए और 7,250 करोड़ रुपए तक का योगदान करने की मंशा रखते हैं। शेयरधारकों ने यह भी कहा कि यदि राइट इश्यू का कुछ हिस्सा नहीं बिक पाता है तो वे उस बचे हुए हिस्से के पूरे या उसके कुछ भाग को खुद खरीदने का अधिकार अपने पास रख रहे हैं। मुंद्रा ने विश्लेषकों से कहा कि 27,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च में उस क्षमता को शामिल नहीं कि गया है,।

जो कि वोडाफोन और आइडिया के बीच परिचालन के तालमेल से उपकरणों को फिर से उपयोग में लाने से बनेगी। इस तरह की क्षमता का मूल्यांकन 6,200 करोड़ रुपए किया गया है।

आईटीजी ने खोली अपनी वेबसाइट, पतंजलि को मिलेगी कड़ी टक्कर

बिजनेस डेस्क।

रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनियों (एफएमसीजी) में आगे निकले की होड़ में आईटीसी ने बड़ा कदम उठाया है। अब वह अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट लाएगी, जिससे उसके उत्पाद ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। कंपनी के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर बी सुमंत ने बताया कि यह फैसला तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन कारोबार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बता दें कि कंपनी पहले से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्मस पर अपना सामान बेच रही है। हाल में आई नेलस्न की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में एफएमसीजी सेल्स में ई-कॉमर्स का शेयर पिछले दो सालों में तीन गुना बढ़ गया है। इस वक्त देश में करीब 98 प्रतिशत उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट है, जिसकी मदद से वह जरूरत की चीजों को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसे देखते हुए आईटीसी ने वेबसाइट लॉन्च की है। फिलहाल यह वेबसाइट दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में ही चलेगी। यहां सफल होने के बाद इस प्रयोग को आगे फैलाया जाएगा। पैकेजड फूड, पर्सनल केयर और स्टेशनरी के प्रॉडक्टस बेचने वाली कंपनियों में आईटीसी 2030 तक भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है।

आईटीसी के वेबसाइट खोलने के कदम से बाबा रामदेव के ब्रैंड पतंजलि को कड़ी टक्कर मिल सकती है। पतंजलि पहले से वेबसाइट बनाकर पर उसपर अपने उत्पाद बेच रहा है। हालांकि, साल 2018 उनके लिए भी खास अच्छा नहीं रहा।

जीएसटी और कॉम्पिटीशन के चलते पिछले साल पतंजलि के बिजनेस को चोट पहुंची और 2013 के बाद उसने सबसे खराब प्रदर्शन किया था। रिसर्च प्लैटफॉर्म टॉफलर से मिले फाइनैंशल डेटा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2017-18 में पतंजलि की आमदनी 10 फीसदी गिरकर 8,135 करोड़ रुपए रह गई,। जो सालभर पहले 9,030 करोड़ रुपए थी।

19 फरवरी से लागू हो जाएगा पैनिक बटन, इन महिलाओं को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली।

मुसीबत में फंसी महिलाओं और बच्चों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए सरकार ऐतिहासिक डिजीटल कदम उठाने जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 19 फरवरी से मोबाइल फोन में पैनिक बटन को अनिवार्य करने जा रहा है। यह बटन हर मोबाइल में होगा। आमतौर पर दो तरह के पैनिक बटन होते हैं जो मुसीबत के वक्त बड़े काम के साबित होते हैं। करीब 3 साल पहले महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव पेश किया था। महिलाओं को किसी भी राज्य में सुरक्षा या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आपात स्थिति आए तो वह अपने फोन में 112 नम्बर (पैनिक बटन) को डायल कर पुलिस की मदद मांग सकती है। इस नम्बर को दबाते ही नजदीक वाली पुलिस की मोबाइल वैन को स्वतः यह संदेश चला जाएगा कि किस जगह पर कोई महिला परेशानी में है। पैनिक बटन से आपात स्थिति में मदद के लिए महिला ने अपने जिन 5 करीबियों का फोन नम्बर रखा होगा, उनको भी संदेश मिल जाएगा। सबसे बेसिक पैनिक बटन किसी थैफ्ट अलार्म की तरह काम करते हैं। आपने बटन दबाया और सायरन की तरह जोरदार आवाज, आसपास के लोगों का ध्यान खींच लेती है और बटन दबाते ही मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सिस्टम को खड़ा करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया कोष से 321 करोड़ रुपए दिए हैं। पैनिक बटन का एक राज्य में प्रयोग करके व्यावहारिक कठिनाइयों को समझा गया। प्रयोग सफल रहा, फिर भी कुछ समस्याएं बनी रहीं। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी इसे तभी उपयोगी मानती थीं, ।

आईएमएफ ने वृद्धि धीमी रहने पर वैश्विक आर्थिक 'बंवडर' उठने की दी चेतावनी

दुबई।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने रविवार को दुनिया भर की सरकारों को सावधान करते हुए आर्थिक वृद्धि उम्मीद से कम रहने पर उठने वाले बंवडर का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लगार्ड ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में कहा, 'हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं जो अनुमान से भी कम रफ्तार से वृद्धि कर रही है।' आईएमएफ ने पिछले महीने ही इस साल की वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 3.7 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया था। लगार्ड ने उन कारकों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुस्त पडने की वजह बताया जिन्हें वह अर्थव्यवस्था के ऊपर मंडराने वाले 'चार बादल' बताती रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि तूफान कभी भी उठ सकता है। उन्होंने कहा कि इन जोखिमों में व्यापारिक तनाव एवं शुल्क बढना, राजकोषीय स्थिति में सख्ती, ब्रेक्जिट को लेकर अनिश्चितता तथा चीन की अर्थव्यवस्था के सुस्त पडने की रफ्तार तेज होना शामिल है। उन्होंने कहा कि विश्व की दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं अमरीका और चीन के बीच जारी

शुल्क युद्ध का वैश्विक असर दिखने लगा है। उन्होंने सरकारों को संरक्षणवाद से बचने की सलाह देते हुए कहा, 'हमें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि यह किस तरह समाप्त होने वाला है और क्या यह व्यापार, भरोसा और बाजार पर असर दिखाने की शुरुआत कर चुका है।' लगार्ड ने कर्ज की बढ़ती लागत को भी जोखिम बताया।

संक्षिप्त समाचार

पायलट्स की कमी के कारण इंडिगो ने कैंसल की 30 फ्लाइट्स!

मुंबई। किफायती विमानन कंपनी इंडिगो ने देशभर में कई फ्लाइट्स कैंसल करने की जानकारी दी है। इसके पीछे क्रू की कमी की बात सामने आई है। हालांकि, इंडिगो ने इस पर कुछ नहीं कहा है। हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर से ऑपरेट होने वाली बहुत सी फ्लाइट्स को शनिवार और रविवार को भी कैंसल किया गया था, अब सोमवार को भी करीब 30 फ्लाइट्स कैंसल होने की बात कही जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, चेन्नई से आठ, हैदराबाद से छह और जयपुर से तीन फ्लाइट्स को बीते शनिवार और रविवार को कैंसल किया गया था। फ्लाइट कैंसल होने के पीछे वजह बताते हुए एक सूत्र ने कहा, रोस्टर के हिसाब से पायलट्स को साल में 1 हजार घंटे से ज्यादा उड़ान नहीं भरवाई जा सकती। इंडिगो के कई पायलट्स अपनी लिमिट पूरी कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें फिलहाल उड़ान नहीं भरने दी जा सकती। हालांकि, इंडिगो ने पायलट्स की कमी पर कुछ नहीं कहा है। उनका कहना है कि फ्लाइट खराब मौसम के चलते कैंसल हुई हैं। इंडिगो ने अपने बयान में कहा, शुक्रवार को उत्तर भारत में आए तूफान की वजह से इंडिगो की 11 फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा। आने वाले दिनों में भी हमें ऐसे ही काम करना पड़ा था। शेड्यूल को फिर से बनाने की वजह से क्रू और एयरक्राफ्ट की टाइमिंग में भी बदलाव किए जा रहे हैं।

कोकोनिक्स ने लॉंच किये भारत निर्मित लैपटॉप

नयी दिल्ली । सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सुयंक्त उपक्रम कोकोनिक्स ने मेड इन इंडिया लैपटॉप लॉंच करने की घोषणा की है। कंपनी ने सोमवार को यहां एमएआईटी द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शिखर सम्मेलन में इस लैपटॉप को लॉंच किया जो चालू वर्ष की दूसरी तिमाही से बाजार में उपलब्ध होगा। कोकोनिक्स यूटीएस ग्लोबल, केलट्रॉन, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) और एक्सीलेरॉन लैब्स का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी का विनिर्माण संयंत्र तिरूवन्तपुरम में है। कंपनी ने तीन लैपटॉप प्रदर्शित किये जिसमें सीसी11बी, सीसी11ए और स314ए शामिल है। ये लैपटॉप सरकारी संस्थानों, उद्यमों और शैक्षिक संस्थानाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किये गये हैं। उसने कहा कि इसकी कीमतें प्रतिस्पर्धी रखी जायेगी। इस शिखर सम्मेलन में 30 बड़ी कर्पनियों के करीब 300 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

2 दिन बाद फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

बिजनेस डेस्क। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सोमवार को फिर से बढ़ौतरी हुई। दो दिनों की गिरावट के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल आज 5 पैसे महंगा हुआ और डीजल में भी 6 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती-घटती कीमतों के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी इसका असर दिख रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनियाभर की आर्थिक ग्रोथ को लेकर जारी चिंता का असर कच्चे तेल पर है। अगर दुनिया में आर्थिक ग्रोथ धीमी रहती है तो मैन्युफैक्चरिंग और अन्य गतिविधियां भी धीमी हो जाएंगी। लिहाजा कच्चे तेल की डिमांड में कमी आएगी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 70.33 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत में 72.44 रुपए प्रति लीटर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 75.97 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में पेट्रोल 73.00 रुपए प्रति लीटर पर है। डीजल की कीमतें दिल्ली 65.62, कोलकाता में 67.40, मुंबई में 68.71 और चेन्नई में 69.32 रुपए प्रति लीटर पर बनी हुई हैं।

मात्र 53 महीनों में जन धन खातों में जमा हो गए करीब 90,000 करोड़ रुपए

नई दिल्ली।

करीब 53 महीने पहले शुरू हुई जन धन खाता योजना के खुले हुए खातों में करीब 90,000 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। वित्त मंत्रालय की मानें तो जल्द ही इन खातों में 1 लाख करोड़ रुपए पार हो जाएंगे। इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा कवर को दोगुना करने के बाद इन खातों में जमा राशि और भी ज्यादा बढनी शुरू हो गई। इसके बाद यह बात सामने आई। खासकर मार्च 2017 से जन धन खातों में जमा में तेजी आई है। इन खातों में 30 जनवरी 2019 तक कुल जमा बढ़कर 89,257.57 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। जमा में वृद्धि जारी है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से जन धन खातों के आंकड़े जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 23 जनवरी को जन धन खातों में कुल जमा 88,566.92 करोड़ रुपए था। इस योजना की सफलता को देखते हुए केन्द्र सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। वहीं ओवरड्राफ्ट की सीमा को दोगुना करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोडने के उद्देश्य से केन्द्र ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरूआत की थी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 34.14 करोड़ खाते खोले गए हैं। इन खातों में औसत जमा बढ़कर 2,615 रुपए हो गया, जो 25 मार्च 2015

को 1,065 रुपए पर था। इन खातों में 53 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं, जिनमें से 59 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र से हैं। आंकड़ों के मुताबिक 27.26 करोड़ खाताधारकों को दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपे डैबिट कार्ड जारी किए गए हैं।

फंसे घर बनाने के लिए केंद्र सरकार देगी आर्थिक मदद, आम्रपाली पर होगा फोकस

बिजनेस डेस्क।

आम्रपाली समेत दूसरे बिल्डरों से घर खरीदकर अगर आप भी फंस गए हैं तो आपके लिए बड़ी राहत है। केन्द्र सरकार इन डूबी आवासीय परियोजनाओं को उबारने की योजना पर काम कर रही है। सरकार बैंकों के माध्यम से करीब 1,000 करोड़ रुपए बतौर संकट निधि (स्ट्रेस फंड) मुहैया करवाएगी। अगले दो सप्ताह में यह फैसला होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार आम्रपाली पर फोकस कर रही है। आम्रपाली और जेपी इंफ्राटेक पर आए संकट से करीब एक लाख खरीदारों को उबारने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति का गठन किया था। समिति ने सरकार को पिछले साल अगस्त में रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बैंकों के माध्यम से आर्थिक मदद दे। अब इस मसले में तेजी आई है। शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस मुद्दे पर 2 फरवरी को बैठक हो चुकी है। खरीदारों की संस्था नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि उन्हें मंत्रालय के उच्चस्तरीय अधिकारी ने बताया कि स्ट्रेस फंड देने के लिए सहमति बन चुकी है। जल्द सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। सबसे पहले आम्रपाली बिल्डर के डूबे प्रोजेक्ट उबारे जाएंगे। फ्लैट खरीदारों की याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। खरीदारों का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि सरकार को स्ट्रेस फंड देने के लिए आदेश दें। अब तो आम्रपाली बिल्डर की संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है। खरीदार भी आ रहे हैं। अब अगर सरकार स्ट्रेस फंड देती है तो उसका पैसा आसानी से निकल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) बिल्डर की संपत्तियों को नीलाम करके पैसा अर्जित कर रहा है। यह पैसा एनबीसीसी को देकर अधूरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाया जाएगा। खरीदार करीब दो वर्षों से स्ट्रेस फंड देने की मांग सरकार से कर रहे हैं। इन लोगों को उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में सरकार प्रावधान करेगी। लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। तब से खरीदार कड़ी नाराजगी जता रहे हैं।

यात्रियों को वंदे भारत एक्सप्रेस में देना होगा खाने का चार्ज,

नई दिल्ली। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 में यात्रियों के लिए खाद्य पदार्थ उनके टिकट का हिस्सा होगा। यानी वह इसे विकल्प की तौर पर 'चुन या हटा' नहीं सकते हैं, जैसा कि शताब्दी, राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस में होता है। अधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को यह जानकारी दी। हालांकि इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन से इलाहाबाद से वाराणसी की यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट बुक कराने के दौरान खाद्य पदार्थ चुनने या नहीं चुनने की सुविधा होगी। यह भोजन भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की ओर से मुहैया कराया जाएगा। कैटरिंग शुल्क उनके टिकट में शामिल नहीं होगा। यह ट्रेन अपनी पहली यात्रा 15 फरवरी को शुरू करेगी। सूत्रों ने बताया कि यात्री अगर टिकट बुक कराने के दौरान भोजन का विकल्प नहीं चुनते हैं, लेकिन वह यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थ चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए अतिरिक्त 50 रुपये देने होंगे। आईआरसीटीसी ने 2017 में राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में पैंट्री सिंवस वैकल्पिक कर दिया था। ऐसा यात्रियों से ज्यादा शुल्क वसूलने और गुणवत्ता तथा मात्रा की समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए किया गया था। वहीं ट्रेन18 के बारे में एक अधिकारी ने कहा, ''स्टेशनों के बीच कैटरिंग शुल्क तय कर दिया गया है और यह सभी यात्रियों के टिकट शुल्क में जोड़ा जाएगा।'' ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया प्रीमियम ट्रेनों के मुकाबले अधिक होगा। ट्रेन अपनी 755 किलोमीटर की यात्रा में दो स्टेशनों कानपुर और प्रयागराज में रूकेगी।

कार-बसों में इस्तेमाल होगा नया ईंधन, नहीं होगा प्रदूषण,

ग्रेटर नोएडा । देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सीएनजी में हाइड्रोजन मिलाकर एचसीएनजी तैयार किया है जो वर्तमान इंजनों पर भी बीएस-6 उत्सर्जन के लगभग सभी मानकों को पूरा करेगा। आईओसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजीव सिंह ने रविवार को ग्रेटर नोएडा में शुरू हुए तीन दिवसीय सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 में बताया कि कंपनी ने सीएनजी में 18 प्रतिशत हाइड्रोजन मिलाकर एचसीएनजी तैयार किया है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड को छोड़कर अन्य सभी प्रदूषकों के मामले में भारत स्टेज-6 पर खरा उतरता है। देश में बीएस-6 अगले साल 01 अप्रैल से लागू होना है। उन्होंने कहा, इस समय उर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। शेल गैस की प्रौद्योगिकी ने पिछले चार-छह साल में पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। इससे कीमतों पर नकारात्मक असर जरूर पड़ा, लेकिन साथ ही दक्षता भी बढ़ी। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई और प्रौद्योगिकी अचानक सामने आ जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में सेक्टर को टिकाऊ उत्पाद पेश करना होगा जो पर्यावरण के अनुकूल भी हो। मसलन आज के समय में यूरो-6 मानक वाले पारंपरिक वाहन इंजन सीएनजी इंजनों के समान ही कम प्रदूषण करने वाले हैं। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के छाने से पहले ही उनसे ज्यादा दक्ष पारंपरिक इंजन बाजार में आ जाएं। सिंह ने बताया कि एचसीएनजी तैयार करने की आईओसीएल की प्रौद्योगिकी का पेटेंट हो चुका है। जल्द ही दिल्ली में एक डीटीसी बस डिपो से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद इसका विस्तार किया जायेगा।

विदेश में इनडायरेक्ट इनवेस्टमेंट पर आयकर विभाग की नजर

मुंबई।

विदेश में शेयरों और प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले या विदेशी ट्रस्टों के बेनेफिशियरी में शामिल अमीर भारतीयों की ओर आयकर विभाग की नजर घूमी है। विभाग उनसे जानना चाहता है कि अपने इनडायरेक्ट इनवेस्टमेंट्स की जानकारी इन लोगों ने क्यों नहीं दी। अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी कंपनी में स्टेकहोल्डर हो और वह कंपनी दूसरी विदेशी कंपनियों में निवेश करे तो ऐसा निवेश भारतीय व्यक्ति का इनडायरेक्ट इनवेस्टमेंट कहा जाएगा। अगर किसी शख्स की दुबई में किसी अनलिस्टेड विदेशी कंपनी ए में 15 प्रतिशत हिस्सा हो और वह कंपनी तीन अमेरिकी कंपनियों बी, सी और डी में शेयरहोल्डर हो तो टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार बी, सी और डी में इनडायरेक्ट ओनरशिप का खुलासा इनकम टैक्स रिटर्न में कंपनी ए में किए गए निवेश की जानकारी देने के साथ किया जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि विभाग ने कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से सवाल किया है कि उन्होंने अपने इनडायरेक्ट इनवेस्टमेंट की जानकारी क्यों नहीं दी, जबकि कानून के मुताबिक बतौर इंडियन रेजिडेंट वे सभी कंपनियों के अल्टीमेट बेनेफिशियल ओनर हैं। ऐसी जानकारी न देने पर कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और अगर टैक्स डिपार्टमेंट जवाब से संतुष्ट न हो तो वह ब्लैक मनी से जुड़े नए कानून के तहत कदम उठा सकता है। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट दिलीप लखानी ने कहा, बेनेफिशियल ओनरशिप की परिभाषा देने के लिए इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 139 को बदला गया था। इनडायरेक्ट ओनरशिप को भी इस परिभाषा के दायरे में लिया गया है। यह परिभाषा पहली अप्रैल 2016 से लागू हुई थी। भारत से बाहर किसी स्ट्रक्चर में किए गए ऐसे निवेश को इसमें कवर किया गया है, जिससे बाद में दुनिया में कहीं भी दूसरे स्ट्रक्चर्स में निवेश किया गया हो।

डॉलर के मुकाबले रुपये में बनी रही मजबूती

नई दिल्ली । डॉलर के मुकाबले रुपये में सोमवार को भी मजबूती बनी रही। पिछले कारोबारी सत्र से आठ पैसे की बढ़त के साथ रुपया डॉलर के मुकाबले 71.23 पर खुला। हालांकि बाद में रुपया थोड़ा फिसलकर 71.25 पर आ गया। दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत होने के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपये में यह तेजी देखी जा रही है। मुद्रा बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, विदेशी निवेश की आमद और कच्चे तेल के दाम में गिरावट से रुपये को सपोर्ट मिला है। उधर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी रहने की आशंकाओं से डॉलर में निवेश के प्रति निवेशकों का रुझान बढ़ने से डॉलर प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है,।

सूरत, उधना, नवसारी रेल्वे स्टेशनों पर यात्रियों को हो रही समस्याओं का हल निकालने की रखी मांग

सूरत। जेडआरयुसीसी के सदस्य छोटुभाई पाटिल, अनुरागभाई कोठारी और संतोषभाई शाह ने मुंबई में आयोजित 33वें जोनल रेल्वे युजर्स कन्सलटेटीव कमिटी की बैठक में उपस्थित रहे थे। बैठक से पहले ये तीनों सदस्य सांसद सी.आर.पाटिल के साथ चर्चा करने के बाद दक्षिण गुजरात के सूरत, उधना, नवसारी समेत रेल्वे स्टेशनों पर यात्रियों को हो रही असुविधाओं, नई ट्रेन, ट्रेन के स्टोपेज और ट्रेनों में कोच की सं या बढ़ाने के लिए वेस्टर्न रेल्वे के जनरल मैनेजर ए.के.गुप्ता से पेशकश की थी। जिसका रेल्वे विभाग द्वारा सकारात्मक प्रतिसाद दिया गया है। इसी के साथ प्रस्तुतियों के संदर्भ में रेल्वे ने काम पूर्ण करने के लिए जेडआरयुसीसी के सदस्यों को निश्चित समय मर्यादा भी दे दी थी।

सूरत रेल्वे स्टेशन के लिए मांग

सूरत से दक्षिण गुजरात के स्टेशनों पर श्रमिकों को ले जाने वाली और वापी से सूरत लाने वाली लाइंग रानी व वापी से सयाजी नगरी ट्रेन के बाद इन स्टेशनों को जोड़ने वाली दूसरी ट्रेन नहीं है। ऐसे में जेडआरयुसीसी के सदस्यों ने छोटुभाई पाटिल की अगुवाई में इन विस्तारों के श्रमिकों और पर्यटकों को राहत मिले इस आशय से दोनों ओर से एक-एक नई ट्रेन दौड़ाये जाने की मांग की है।

उधना रेल्वे स्टेशन के लिए पेशकश

उधना यार्ड में रहने वाले लोगों के लिए रेल्वे स्टेशन पर आने और स्टेशन क्रोस कर उद्योगनगर की ओर जाने के लिए वर्षों से रेल्वे फूट ओवर ब्रिज का उपयोग कर रहे हैं। इस ब्रिज को उधना यार्ड तक विस्तृत करने की भी पेशकश की गई थी। रेल्वे विभाग द्वारा इस बात पर ध्यान देते हुए 2019-20 में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए यह कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है।

उधना रेल्वे स्टेशन का महत्तम उपयोग महाराष्ट्र के भुसावल जाने वाले यात्री करते हैं। ताप्तीलाइन पर आनेवाली और जानेवाली सभी ट्रेनों को यदि उधना में स्टोपेज मिले तो सूरत स्टेशन के भार को हल्का किया जा सकता है। महाराष्ट्र की ओर जाने वाले अधिकांश यात्री उधना में रहते हैं, फिर भी उन्हें सूरत स्टेशन तक जाना पड़ता है जिससे अधिक खर्च भी करना पड़ता है। छोटुभाई पाटिल द्वारा की गई पेशकश को ध्यान में रखते हुए रेल्वे विभाग इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है।

उत्तर भारतीयों की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण अवध एक्सप्रेस ट्रेन रात 3 बजे सूरत रेल्वे स्टेशन पर आती है। इतनी रात को उत्तर भारतीय श्रमिक वर्ग को भेस्तान, उधना या पांडेसरा विस्तार से परिवहन की व्यवस्था नहीं मिलती है, जिससे वे रात 10 बजे से सूरत रेल्वे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। इस कारण से सूरत रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों की सं या काफी बढ़ जाती है और इसका लाभ गुनाहीत प्रवृतियों के लोग उठाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए छोटुभाई पाटिल ने अवध एक्सप्रेस को उधना रेल्वे स्टेशन पर स्टोपेज देने की मांग की है, जिससे यात्रियों को सूरत तक नहीं जाना होगा और उन्हें राहत मिलेगी।

सूरत में रहने वालों के लिए उधना-दानापुर एक्सप्रेस और उधना-वाराणसी ट्रेन साप्ताहिक हैं, जिसे प्रतिदिन दौड़ाये जाने की मांग पर अधिक जोर दिया गया है। रेल्वे विभाग ने भी इस पेशकश को काफी गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक रवैया दिखाया है।

उधना रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती सं या को देखते हुए, उधना रेल्वे स्टेशन के विकाश पर जोर दिया गया है। स्टेशन के विकास के साथ-साथ रेल्वे प्लेटफॉर्म रेल्वे के डिब्बों की ऊंचाई से नीचे है और ट्रेन की लंबाई से छोटा है। तो उधना स्टेशन की हाइट और ऊंचाई भी बढ़ाने की मांग की गई है।

सचिन रेल्वे स्टेशन पर रिजर्वेशन टिकीट बुकिंग काउन्टर और करन्ट बुकिंग काउन्टर एक ही विन्डो से होता है, जिससे यात्रियों को काफी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इन टिकीट विन्डो को अलग-अलग करने की भी मांग की गई है।

सचिन रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस को सचिन रेल्वे स्टेशन पर स्टोपेज देने की मांग की गई है।

सचिन रेल्वे स्टेशन का लेटफोर्म रेल्वे की सामान्य लंबाई से छोटा है, जिससे ट्रेन के लगभग 6 डिब्बे बाहर रह जाते हैं। सचिन रेल्वे स्टेशन की लंबाई को बढ़ाने और फूट ओवर ब्रिज को स्टेशन से बाहर तक ले जाने की पेशकश भी की गई है।

नवसारी रेल्वे स्टेशन के लिए मांग

नवसारी रेल्वे स्टेशन पर 1 नंबर के प्लेटफोर्म पर सेकन्ड क्लास के यात्रियों के लिए वेइटिंग रूम की व्यवस्था नहीं है। साथ-साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच बेरिकेटिंग की सुविधा भी नहीं है, जिससे अनेक यात्रियों को प्लेटफॉर्म पार करते वक्त अपनी जान गवानी पड़ती है। दोनों प्लेटफॉर्म के बीच बेरिकेटिंग करने की मांग की गई है।

डिंडोली रेल्वे स्टेशन के लिए मांग

जेडआरयुसीसी के सदस्य संतोष शाह ने विकसीत हो रहे डिंडोली के लिए नए रल्वे स्टेशन की बिल्डिंग की मांग की है।

बिलीमोरा रेल्वे स्टेशन के लिए मांग

बिलीमोरा रेल्वे स्टेशन की लंबाई भी ट्रेन की लंबाई से कम है, जिससे ट्रेन के लगभग 6 डिब्बे प्लेटफॉर्म से बाहर रहते हैं। रेल्वे युजर्स कमिटी द्वारा जेडयुआरसीसी के सदस्यों को 2019-20 में प्लेटफॉर्म बढ़ाने का आश्वास दिया गया है।

ट्रेन को रोजाना दौड़ाये जाने की मांग

अमरावती एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन आती है। इस ट्रेन को रोजाना दौड़ाये जाने की मांग कीगई है।

कोट बढ़ाने की मांग

भुसावल पैसेंजर ट्रेन में रिजर्वेशन के दो कोच में 1 कोच की बढ़ोतरी कर तीन कोच करने की मांग जेडयुआरसीसी के सदस्यों द्वारा की गई थी।

महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिला आरपीएफ की मांग

जेडआरयुसीसी मे बर्स द्वारा सूरत समेत दक्षिण गुजरात के सभी रेल्वे स्टेशनों पर महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ में महिला कॉन्स्टेबल की सं या में बढ़ोतरी करने की मांग की गई है।

गोडादरा में भव्य वसंत पंचमी उत्सव मनाया गया

सूरत। नामदेव छीपा समाज (द.गुजरात) द्वारा हर साल की तरह सूरत में संत नामदेव के ज्ञानोदय दिन के उपलक्ष्य में गोडादरा रोड स्थित आस्तिक पार्टी प्लाट पर वसंत पंचमी उत्सव धामधूम से मनाया गया ढ्ढ सुबह 7.00 से शाम 9.00 बजे तक आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे दिन शोभा यात्रा, कलश यात्रा, भजन संध्या, महा आरती, पुरस्कार वितरण, महा प्रसादी जैसे बहुविध कार्यक्रम आयोजित किये गए ढ्ढ वसंत पंचमी उत्सव में सभी छीपा समाज (द.गु.) सहित देश के विभिन्न राज्यों जैसे इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद से आमंत्रित लोगो ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सराहना की इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित पुलिस विभाग में रजत पदक विजेता मित्तलबेन कांतिलाल परमार और इंडियन आइडल प्रतियोगिता के द्वितीय रनर अप गौरवजी को सम्मानित किया गया।

समाज अध्यक्ष फुटरलालजी चौहान, सचिव सुरेश परमार, कोषाध्यक्ष शांतिलाल गहलोतजी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम को अमृतजी, हरीशजी, जगदीशजी, दिनेशजी भाटी, आकाश भाटी, गोविंदजी, रामलालजी, गिरीशजी, मनोजजी गहलोत, मुकेशजी गहलोत, परवीनजी पहाड़िया, अजय नामदेव, भोजराजजी नामदेव, कालूजी, अश्विनजी भाटी, इंद्रमलजी, लोकेशजी, मनीष सोलंकी, दलपतजी, रामनारायणजी, हीरालालजी चौहान, मनोजजी नागर, राजेशजी पिरिया, सुमेरजी पिरिया और गोपालजी नागर ने सफल बनाया।

सूरत। शहर के गोडादरा विस्तार में महाराणा प्रताप चौक पर बी.आर.टी.एस बस में चढते वक्त पैर फिसलने से एक व्यक्ति के पैरों को उपर बस का टायर चढने से उसका एक पैर कट गया और दुसरा पैर बुरी तरह से घायल हो गया।

3.50 करोड़ की पुराने नोट के साथ चार गिरफ्तार

सूरत। नवसारी लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) ने जिले के उडाच गांव के निकट से रु. 3.50 करोड़ की 500 और 1000 के दर की पुराने नोटों के साथ चार श सों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है।

रु. 500 और रु. 1000 के दर के नोटों पर प्रतिबंध लगे दो साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ऐसे नोटों की बरामदगी की सिलसिला थमा नहीं है। आए दिन पुराने नोट पकड़ी जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले के नेशनल हाईवे सं या 48 पर वलसाड और नवसारी जिले के बीच उडाच गांव है। जहां के हाईवे से महाराष्ट्र पासिंग की एक कार पुराने नोटों के साथ गुजरने की सूचना लोकल क्राइम ब्रांच को मिली थी। जिसके आधार पर एलसीबी ने हाईवे पर निगरानी बढ़ा दी। उस वक्त वहां से गुजर रहे महाराष्ट्र पासिंग की एक कार को रोक उसकी तलाशी ली। जिसमें करीब रु. 3.50 करोड़ के रु. 500 और रु. 1000 के पुराने नोट बरामद हुए। एलसीबी ने कार में सवार चार श सों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। जिसमें पता चला कि बरामद नोट मुंबई के अलग अलग जगह से लेकर आए थे।

एएमटीएस बस सेवा कर्जे के तहत : २६.९१ अरब का कर्जा

अहमदाबाद। एक समय में देशभर में प्रतिष्ठित वाली और शहर की पहचान समान ऐसी लाल बस के तौर पर जानी जाती अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस (एएमटीएस) निजीकरण होने से अब कभी भी दिवालियापन दर्ज कराये ऐसी बेबस और बदतर हालत में आ चुकी है। एएमटीएस संस्था का प्रतिदिन बढ़ रहा कर्जा अब इतने हद तक बढ़ गया है कि, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यह कर्जा कचरे के ढेर से भी ज्यादा विशाल बन गया है। गत ३१ दिसम्बर, २०१८ की तारीख में एएमटीएस पर अभी तक का प्रशासन का कुल २६९१ करोड़ रुपये यानी कि २६ अरब, ९१ करोड़ का कर्जा हो गया है यानी कि एएमटीएस बस के टायर तो क्या स्टियरिंग भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्जे में डूबे है।

चुनाव तैयारी जारी : आज अमित शाह की अध्यक्षता में सम्मेलन होगा

अहमदाबाद। भाजपा मीडिया सेल की सूची बताती है कि, भाजपा द्वारा १२ फरवरी से पूरे देश में 'मेरा परिवार- भाजपा परिवार' अभियान शुरू होने जा रहा है। जिसके तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद में सुबह में ९ बजे अपने आवास से भाजपा का झंडा फहराया जाएगा।

इसके बाद सुबह में १० बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ओडिटोरियम अहमदाबाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 'मेरा परिवार- भाजपा परिवार' के देशव्यापी अभियान का शुभारंभ करके देशभर के कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मार्गदर्शन देंगे। उपरोक्त कार्यक्रमों में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा चुनाव प्रभारी ओमजी

माथुर, प्रदेश अध्यक्ष जीतु वाघाणी, मुख्यमंत्री विजय रुपाणी तथा उपप्रमुख मुख्यमंत्री नीतिन पटेल तथा प्रदेश अग्रणी, अहमदाबाद जिला-महानगर के सीनियरों सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। प्रदेश भाजपा मीडिया सेल की सूची बताती है कि,, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में १२ फरवरी, २०१९ को गोधरा में पंचमहाल, दाहोद और छोटाउदेपुर लोकसभा सीटों की कलस्टर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दोपहर में २ बजे एसआरपी. ग्राउंड, शहेरा रोड, गोधरा में प्रारंभ होने वाले कलस्टर सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष जीतु वाघाणी, मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, केंद्रीय मंत्री जसवंतसिंह भाभोर तथा प्रदेश के सीनियर उपस्थित होकर मार्गदर्शन देंगे।

इस कलस्टर सम्मेलन में लोकसभा सम्मेलनों में लोकसभा मतक्षेत्र के लोकसभा सीट के प्रभारी, इंचार्ज-सहइंचार्ज, लोकसभा सीट का विस्तार, संकलन समिति के सदस्यों, प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश कारोबारी सदस्यों, मंडल पदाधिकारी, स्थानीय स्वराज्य में चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों, प्रदेश और जिला/महानगर के मोर्चा पदाधिकारियों, मंडल मोर्चा के प्रमुख-महामंत्रियों, शक्तिकेंद्र के इंचार्ज-प्रभारी, बोर्ड-निगम के पदाधिकारियों तथा पूर्व सांसद-विधायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित होंगे।

पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर अलग-अलग कार्यक्रम होंगे

अहमदाबाद। प्रदेश भाजपा मीडिया सेल की सूची बताती है कि, ११ फरवरी 'समर्पण दिवस' एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान के दिन गुजरात भाजपा द्वारा पूरे राज्य में पुष्पाजंलि के कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। समर्पण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी तथा प्रदेश अध्यक्ष जीतु वाघाणी सहित भाजपा के हजारों कार्यकर्ता नमो एप के माध्यम से ५ रुपये से लेकर १००० रुपये तक की रकम भाजपा संगठन को समर्पण निधि के रूप में अर्पित की। गुजरात भाजपा द्वारा पुष्पाजंलि कार्यक्रम के साथ गुजरात के हरएक बूथ में कम से कम दो कार्यकर्ता नमो एप के माध्यम से समर्पण निधि अर्पित करे इस प्रकार के कार्यक्रम समर्पण दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया जिसके तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीतु वाघाणी ने वडोदरा में आकोटा विधानसभा के वोर्ड नंबर १३ के बूथ नंबर १९३ पर उपस्थित होकर पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी को पुष्पाजंलि अर्पित करके समर्पण निधि कार्यक्रमों का प्रारंभ कराया गया। जिसमें प्रदेश सीनियरों तथा वडोदरा शहर-जिला भाजपा के सीनियरों तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)